शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 7 – 14 अगस्त 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या सुक्खू सरकार संकट में है

- विधायकों और पूर्व विधायकों की प्रतिक्रियाओं से उठी चर्चा
- हर चुनावी सर्वेक्षण में आ रही कांग्रेस की हार
- हाई कमान ने लिया कड़ा संज्ञान

शिमला/शैल। पिछले दिनों जिस तरह के ट्वीट कांग्रेस विधायको राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के आये हैं उससे राजनीतिक हल्कों और प्रशासनिक गलियारों में जो चर्चाएं चल निकली हैं यदि उन्हें अधिमान दिया जाये तो निश्चित रूप से सुक्खू सरकार सियासी संकट में फंस चुकी है। क्योंकि आठ माह में सुक्खू अपने मंत्रीमंडल के तीन रिक्त स्थानों को नहीं भर पाये हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का भी एक पद खाली चला आ रहा है। इन खाली पदों को एक समय सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक कुछ लोगों ने माना था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में जब सुक्खू ने मंत्रीमंडल के विस्तार से पहले ही छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर ली तब यह स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार एक कूटनीति की शिकार हो गई है और कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पायेगी । क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां संविधान के अनुरूप नहीं है। इन नियुक्तियों को एक दर्जन भाजपा विधायकों सहित तीन याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह फैसला जब भी आयेगा इनके खिलाफ ही आएगा। पहले भी उच्च न्यायालय ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय भी इन्हें असंवैधानिक करार दे चुका है। कानून की यह जानकारी होने के बावजूद भी ऐसी नियुक्तियां करना क्या दर्शाता है यह अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों से पूर्व यह फैसला आना तय है।

मंत्रियों के तीन पद खाली रखते हुए एक दर्जन के करीब गैर विधायकों को कैबिनेट रैंक में ताजपोशी देना सुक्खू सरकार का और बड़ा फैसला है। इन ताजपोशियों में भी अकेले जिला शिमला को 90% स्थान दिया गया है। इन ताजपोशियों से ही यह आरोप लगा है कि यह सरकार मित्रों के से घिरकर रह गई है। क्योंकि यह ताजपोशियां पाने वाले संगठन के कोई बड़े पदाधिकारी भी नहीं रहे हैं और विधानसभा चुनावों में भी इनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। ऐसे राजनीतिक फैसलों का पार्टी के विधायकों और दूसरे कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा इसका भी अन्दाजा लगाया जा सकता है। इन फैसलों से हटकर यदि सरकार के मंत्रियों और उनकी कार्य स्वतंत्रता की बात की जाये तो जब शिमला में टैक्सी यूनियन विवाद खड़ा हुआ तब सरकार के मंत्री एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हो गए। उसके बाद जब यह आपदाएं और जगह-जगह भूस्खलन और बाढ़ का प्रकोप घटा तब एक मंत्री ने इसके लिए जब अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया तब दूसरे मंत्री ने इस ब्यान को ही बचकाना करार दे दिया। यही नहीं जब विक्रमादित्य सिंह केंद्र में नितिन गडकरी और अन्य मंत्रियों से मिले तब यह सामने आया कि विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को अधिकारियों के स्तर पर बदल दिया गया है। इस पर विक्रमादित्य सिंह को एक पत्रकार वार्ता में अधिकारियों को संदेश देना पड़ा कि वह लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास न करें। इस तरह राजनीतिक स्तर पर आठ माह की जो कारगुजारियां रही हैं उसमें व्यावहारिक तौर पर संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव रहा है। पार्टी अध्यक्षा इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाई कमान के संज्ञान में ला चुकी है। प्रशासन पर अभी भी भाजपा का प्रभाव कितना है इसका अंदाजा मंत्री पुत्र पूर्व विधायक नीरज भारती के ट्वीट से लगाया जा सकता है। इस परिपेक्ष में जब पार्टी के विधायकों से लेकर नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर तक सभी जगह अप्रसन्नता के भाव देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसी स्थिति के कारण कांग्रेस हाईकमान द्वारा करवाए चुनावी सर्वेक्षण में यह सामने आया कि हिमाचल में सरकार होने के बावजूद पार्टी चारों सीट हार रही है। इसी सर्वेक्षण के बाद हाई कमान ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह को हालात की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कौल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार 23 विधायकों ने लिखित में सरकार से नाराजगी व्यक्त की है। अब तो यह सवाल भी पूछा जाने लग पड़ा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री एक समय भाजपा सरकार के प्रति बहुत मुखर होते थे अब चुप क्यों हैं। बल्कि जब उनके ही विभाग से संबंधित जल उपकर आयोग के सदस्यों को शपथ दिलाई गई तब वह उपस्थित क्यों नहीं थे। क्या आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में उनकी सहमति नहीं रही है। अभी 15 अगस्त को जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराने के लिए बिलासपुर में तैनात किया गया है उससे संगठन और सरकार में उभरती दरारें और चौड़ी होने की संभावना बढ़ने के आसार बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपने गैर राजनीतिक सलाहकारों से ऐसे घिर गए हैं कि उन्हें उनके दिखाएं हरे के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बल्कि सही लिखने बोलने वालों को सरकार का दुश्मन माना जा रहा है। चर्चा है कि हाईकमान शीघ्र ही इसका संज्ञान लेकर शीघ्र ही कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। क्योंकि अगर राजनीतिक परिदृश्य के साथ सरकार द्वारा लिये गये अन्य फैसलों पर भी एक साथ नजर डाली जाए तो स्थितियां और भी भयावह हो जाती हैं।

राज्यपाल ने चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षति का लिया जायजा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 05 पर

भारी भूस्खलन के कारण हुई क्षति का जायजा लिया और जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश से सेब बाहरी मण्डियों को भेजा जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सेब सही समय पर मण्डियों तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि सेब सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 05 प्रदेश में आवश्यक आपूर्ति तथा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राकृतिक विभीषिका के कारण प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जगह-जगह भूस्खलन एवं बादल फटने से न केवल व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हुई हैं अपितु जन-जीवन भी प्रभावित हुआ है। वह स्वयं अनेक स्थानों का दौरा कर क्षति का जायजा ले रहे हैं।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने अवगत करवाया कि सोलन जिला में अभी तक भारी वर्षा से लगभग 526 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावितों को दी जा रही सहायता राशि एवं जन-जीवन सुचारू बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ए.के. दहिया ने भारी वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग 05 को हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह ठीक करने में 30 से 45 दिन का समय लगेगा। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा इस राजमार्ग को सुचारू बनाए रखने और भविष्य में क्षति से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी।

पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, जिला प्रशासन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने समरहिल में आपदा प्रभावित शिव बावड़ी का दौरा किया

➢ राहत कार्यों का जायजा लिया और सोलन के जादौन का दौरा भी किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के उपनगर समरहिल में शिव बावड़ी का दौरा कर बचाव कार्यों का जायज़ा लिया। इस

अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा भी उपस्थित थे।

सूचना मिलते ही राज्यपाल बालूगंज चौक से पैदल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां की स्थिति देखकर भावुक हो गये।

अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि शिव बावड़ी में बादल फटने से हुई आपदा हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों से जान-माल के नुकसान की जानकारी मिल रही है, लेकिन इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने वहां मौजूद प्रशासन को बचाव कार्य तेज़ करने का निर्देश दिया ताकि मलबे में दबे लोगों को बचाया जा सके।

इसके बाद राज्यपाल सोलन जिला की ममलीग पंचायत के अंतर्गत जड़ोन गांव गये। यहां बीती रात भारी भूस्खलन से एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। राज्यपाल ने दो किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए प्रभावित परिवार के सदस्यों से भेंट की। राज्यपाल ने वहां उपस्थित पूरे गांव वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि इस विपदा की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ है।

राज्यपाल के सचिव भी उनके साथ उपस्थित थे।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राज्य में भारी बारिश के कारण जान-माल के नुकसान को देखते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित होने वाले 'ऐट होम' कार्यक्रम को भी रद्द करने का फैसला किया है।

राज्यपाल ने 74वें वन महोत्सव का शुभारम्भ किया

➢ हिमाचल प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के समीप बाग में देवदार का पौधा रोपित कर 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने भी पौधरोपण किया। जानकी शुक्ल राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष भी हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। लेकिन, जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। उन्होंने कहा कि विकास समय की मांग है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए और साथ ही, हमारा वन क्षेत्र कायम रहना चाहिए। पौधरोपण अभियान में रेडक्रॉस और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी छात्रों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य डॉ.साधना ठाकुर, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल राजीव कुमार, पीसीसीएफ (प्रशासन) अमिताभ गौतम, मानद सचिव राज्य रेडक्रॉस डॉ. किमी सूद और सदस्य भी उपस्थित थे।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल, शिमला का भी दौरा किया और वहां उपचाराधीन लोगों से संवाद किया तथा उन्हें फल भी वितरित किये।

इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे मरीजों को और प्रभावी तरीके से मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ.गोपाल बेरी ने राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक, मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला डॉ. सुरेखा चोपड़ा और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश तथा बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान के दृष्टिगत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल सेरेमोनियल होगें। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण प्रदेश में जानमाल की भारी क्षति हुई है। प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला का दौरा भी किया तथा शिमला शहर के विभिन्न स्थानों में भूस्खलन से घायल हुए लोगों का कुशलक्षेम पूछा तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

नौणी विश्वविद्यालय के 100 छात्रों ने पास की राष्ट्रीय स्तर की नेट परीक्षा

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के तीन घटक महाविद्यालयों के 100 छात्रों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के लिए आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है।

विश्वविद्यालय के बागवानी महाविद्यालय के 67 छात्र, जिनमें सब्जी विज्ञान विभाग और पादप रोग विज्ञान विभाग से 16-16 छात्र, फ्लोरीकल्चर और लैंडस्केप आर्किटेक्चर से 13, व्यवसाय प्रबंधन से 5, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 1 छात्र ने नेट परीक्षा पास की है।

इसके अतिरिक्त वानिकी महाविद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने भी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वानिकी विषयों में, मृदा विज्ञान से 6, सिल्विकल्चर और एग्रोफोरेस्ट्री से 13, सामाजिक विज्ञान से 3 और पर्यावरण, वन उत्पाद और बेसिक साइंस से 2-2 छात्रों और वृक्ष सुधार से एक छात्र ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। हमीरपुर के नेरी में विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से सब्जी विज्ञान के दो और कृषि अर्थशास्त्र और सिल्विकल्चर और एग्रोफोरेस्ट्री विषयों में एक-एक छात्र ने भी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल और कॉलेजों के डीन ने व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से मुलाकात की और उन्हें उनकी उपलब्धि पर बधाई दी।

इस अवसर पर प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में कई राष्ट्रीय परीक्षाओं के अलावा नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल लगभग 72 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों ने फैलोशिप और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को समझने और उसमें सफलता हासिल करने में सक्षम बनाने का प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य से छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए गए ताकि वे इन परीक्षाओं को समझ सकें और उनमें आगे निकल सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

ई-के.वाई.सी. करवाने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत करने व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राशन वितरण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग की जानकारी आधार में दर्ज डेटा के अनुरूप हो।

उन्होंने आग्रह किया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर इस प्रक्रिया को 31 अगस्त, 2023 से पहले पूर्ण करवा लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर राशन कार्ड अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि उपभोक्ता अपना नवीनतम सक्रिय मोबाइल नम्बर विभाग से सांझा कर खाद्यान्नों से सम्बंधित सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। वे विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल https://epds.co.in पर राशन कार्ड में स्वयं अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://epds.co.in पर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नम्बर दर्ज करने के उपरांत अपना मोबाइल नम्बर अपडेट करना होगा।

मुख्यमंत्री ने समरहिल व फागली में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के समरहिल में हुए भारी भूस्खलन के बाद चलाए गए बचाव अभियान के दौरान घटना स्थल का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों का जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री लगभग डेढ़ घंटे तक घटनास्थल पर रुके तथा राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को बचाव कार्यों में और तेज़ी लाने के लिए कहा। राहत एवं बचाव कार्यों में सेना के साथ-साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस एवं होम गार्ड के

जवान और स्थानीय लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सावन के महीने का आखिरी सोमवार होने के चलते लोग समरहिल के शिव मंदिर में आए थे तथा एकाएक यहां भू-स्खलन हो गया जिसके कारण मलबे में कई लोगों के दबने की आंशका है। मलबे से 5 शव निकाले जा चुके हैं और

लोगों को निकालने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटने और भू-स्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इस आपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पिछले माह 7 से 11 जुलाई को हुई बारिश से हुए नुकसान से नहीं उभर पाया था कि पिछले दो-तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण मुसीबते बढ़ गई हैं इस दौरान राज्य में काफी लोगों को जान गंवानी पड़ी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 48 घण्टों से जारी बारिश के कारण सोमवार प्रात: 11 बजे तक पूरे प्रदेश में 21 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है तथा यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। क्योंकि काफी लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए है। वह स्वयं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ निरंतर सम्पर्क में हैं और उनसे पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी सावधान रहने की अपील करते हुए नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी।

समरहिल के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू फागली में हुए भू-स्खलन का जायज़ा लेने पहुंचे। फागली में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पांच लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगाए गए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, उपायुक्त आदित्य नेगी और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

फ्लैगशिप परियोजनाओं से जुड़े एफसीए और एफआरए मामलों के निपटारों में तेजी लाई जाए: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को वन संरक्षण

अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण जैसी महत्वकांक्षी परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभाग से इन परियोजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता प्रदान करने को कहा।

उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्यूलॉजिकल पार्क (चिड़ियाघर) के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने इसके निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रारम्भिक प्रक्रियाएं शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार नियुक्त करने पर बल देते हुए कहा कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटकों को यहां बेहतर अनुभव एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

प्रदेश में ईको-टूरिज्म गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के अग्रणी निजी हित धारकों को आमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश में ईको-टूरिज्म स्थलों को क्लस्टर और व्यक्तिगत स्तर पर निजी कंपनियों को दिया जाएगा जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।

मानसून के दौरान गिरे पेड़ों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को गिरे पेड़ों को हटाकर उनका निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की राजस्व हानि को कम करने की दिशा में गणना, अंकन, निष्कर्ष और निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देने पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पौधरोपण की सफलता के लिए रोपे गए पौधों की जीवन्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जबावदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित सभी ज़िलों में बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले दो दिन से हो रही भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक

41 लोगों की बहुमूल्य जान गई है, जबकि 13 लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए शिमला में बुलाई गई एक आपात बैठक में उन्होंने कहा कि इस भीषण त्रसदी के ष्टिगत इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में सांस तिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में सिर्फ ध्वजारोहण, परेड और मुख्य अतिथि का संबोधन ही होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि परेड में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल नहीं होंगे। वह बचाव कार्यों में ही शामिल होंगे।

मुख्यमंत्रे ने कहा कि भारी बारिश से लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और परेड को भी स्केल डाउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में जवान राहत और बचाव कार्यों में तैनात किए जाएंगे और लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य यु)स्तर पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ से एनडीआरएफ की टुकड़ी शिमला पहुंच गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1200 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 600 सड़कों को आज शाम तक खोल दिया जाएगा और 300 सड़कों को कल तक बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बारिश के कारण जिला सोलन, शिमला, मंडी और हमीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों की हरसंभव मदद प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला शहर में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए और कहा कि गिरे हुए पेड़ों को तुरंत हटा कर सड़कों को बहाल किया जाए। खतरनाक हो चुके पेड़ों को चिन्हित कर सुबह तक उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द बहाल कर लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्रे ने कहा कि प्रदेश भर में बहुत से स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका सम्बन्धित विभाग को अध्ययन करना चाहिए, ताकि इनके कारणों के बारे में पता चल सके।

उन्होंने वीडियो क फेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुद्रों से विद्युत, जलापूर्ति योजनाओं और सड़कों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सोलन के ममलीग में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में भूस्खलन से प्रभावित जड़ोन गांव का दौरा किया। यहां बादल फटने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मृत्यु

हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं। मुख्यमंत्री इस त्रासदी पर भावुक हुए और कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जड़ोन में हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज़िला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं और राज्य सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हादसे में बहुमूल्य जान जाने की पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों के घावों पर मरहम लगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार समुचित आर्थिक मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी आपदा के कारण लोगों को नुकसान हुआ है, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से एक-एक पैसा जुटाकर उनकी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्षों में इस बार सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इसका वैज्ञानिक कारण जानना जरूरी है ताकि सरकार उस पर उचित कारवाई कर जानमाल के नुक्सान को भविष्य में कम कर सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा.(कर्नल) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुख और दु:ख में समान रूप से सहायक होना चाहिए।

– चाणक्य –

सम्पादकीय

मंदिरों में वीआईपी प्रयोग

पिछले दिनों मां चिंतपूर्णी के दरबार में 1100 रूपए की पर्ची कटवाकर श्रद्धालुओं को वी आई पी दर्शन करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। बुजुर्गो और अपंगों के लिए 50 रूपये की पर्ची से यह सुविधा मिलेगी। हर वर्ग के लिए अलग-अलग शुल्क के साथ पर्ची काटी जायेगी। इस फरमान का विपक्षी दल भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। महावीर दल ने इस आश्य का एक ज्ञापन प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भी सौंपा है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी इस फरमान को वापस लेने की मांग की है। लेकिन इस पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिनके पास यह विभाग है उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। इससे यही प्रमाणित होता है कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने की नीयत से यह प्रयोग शुरू किया है। यह प्रयोग मां चिंतपूर्णी से शुरू होकर सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जा चुके अन्य मंदिरों तक भी जायेगा क्योंकि सरकार का नियम सभी जगह एक सम्मान लागू होता है।

हिमाचल में मंदिरों का अधिग्रहण 1984 में विधानसभा में इस आश्य का एक विधेयक लाकर किया गया था। उस समय सदन में इसका विरोध केवल जनता पार्टी के विधायक स्व.राम रतन शर्मा ने किया था। क्योंकि वह स्वयं दियोथ सिद्ध मंदिर के पुजारियों में से एक थे। उसे समय यह आक्षेप लग रहे थे की इन मंदिरों में जितनी आय हो रही है उसके अनुरूप यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। मंदिरों के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। इन आक्षेपों से सभी ने सहमति जताई और यह विधेयक पारित हो गया। उसे समय केवल 11 मंदिरों का अधिग्रहण हुआ था और इन मंदिरों से 8 से 10 करोड़ की आय अनुमानित की गई थी। लेकिन विधेयक का आगे आने वाले समय में विस्तार किये जाने का प्रावधान भी रखा गया था और इस विस्तार का प्रस्ताव जनता पार्टी की विधायक स्व. श्यामा शर्मा की ओर से आया था । यह कहा गया था कि मंदिरों की आय का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाएगा।

इसी विस्तार का परिणाम है कि आज प्रदेश के 35 मंदिरों का प्रबंधन सरकार के पास है और 2018 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एक प्रश्न के उत्तर में आयी जानकारी के अनुसार इन मंदिरों में क्विंटलों के हिसाब से सोना और चांदी जमा है। कैश और एफडी के नाम पर सैकड़ों करोड़ जमा है । प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी एक याचिका के जवाब में इन मंदिरों के पास 2018 में 361.43 करोड़ रूपया होने की जानकारी दी गई है। किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जिलों में यह मंदिर स्थित हैं। इनके प्रबंधन के लिए जिलाधीशों के तहत ट्रस्ट गठित है। सभी मंदिरों में मंदिर अधिकारी तैनात हैं। सभी कर्मचारी सरकारी अधिकारी हैं। अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट का मुखिया हिंदू ही होगा। यदि किसी जिले में गैर हिंदू को जिलाधीश लगा दिया जाता है तो उसे मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है।

इस परिदृश्य में आज की स्थितियों पर विचार किया जाये तो यह सवाल उठता है कि इन मंदिरों के पास जितनी संपत्ति है क्या उसके अनुरूप वहां आने वालों के लिए मंदिर प्रबंधनों द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । क्या प्रबंधनों ने अपने स्तर पर आवासीय सुविधा सुरजीत की हुई है? कितने मंदिर अपने यहां संस्कृत के अतिरिक्त अन्य विषयों का शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस मंदिर पर्यटन के नाम पर एक बड़ा व्यवसाय इन परिसरों के गिर्द खड़ा होता जा रहा है। क्या मंदिरों को पर्यटक स्थलों के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना विकसित करना श्रेयस्कर होगा? क्या मंदिरों और पर्यटक की संस्कृति एक सम्मान हो सकती है? मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह धारणा है कि भगवान के पास सब एक बराबर होते हैं । वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ऊंची और नीचे जाति कोई नहीं होती। वहां पर कोई अधिकारी या सेवक का वर्गीकरण नहीं होता। सबको एक ही लाइन में लगकर दर्शन और पूजा अर्चना करनी होती है। मंदिरों में जब पैसे खर्च करके वीआईपी की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात आएगी तो क्या उससे आम आदमी की आस्था प्रभावित नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी और तब आम आदमी का विश्वास ऐसी व्यवस्था बनाने वालों के प्रति कितना सम्मानजनक रह जाएगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आस्था को पैसों के तराजू पर तोलना घातक होगा।

रेलवे रक्षा जवान द्वारा कत्ल को धार्मिक रंग देना कौम और मादरे बतन दोनों के साथ गद्दारी

गौतम चौधरी

विगत दिनों एक सनसनी मामला सामने आया। मानसिक रूप से अस्वस्थ रेलवे पुलिस बल के एक जवान, चेतन सिंह ने जयपुर-मुंबई सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अपने सीनियर सहित कई दूसरे यात्रियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरोपी चेतन अपने ब्यान में बताया कि ट्रेन में वह सो रहा था तो मृत पिता उसके सपने में आये और कहे कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आये उसे खत्म कर दो। सबसे पहले उसने बी-5 कोच में टॉलेट के पास एएसआई टीकाराम मीणा पर सर्विस राइफल से चार राउंड फायर किया। फिर कोच के दूसरे छोर पर भानुवाला पर फायर किया। इसके अलावा एस-6 कोच में असगर अब्बास पर फायरिंग की और इससे सटे पैंट्री कार में भी एक अन्य यात्री पर गोली चलाई। एस-5 कोच में मीरा रोड से दाहिसर के बीच जब ट्रेंन की जंजीर खींची गई और ट्रेंन रुकी तब चेतन सिंह भागने के फिराक में था लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन ट्रेंन में चेतन जब अपनी राइफल लेकर चढ़ा था तो वह किसी भी यात्री से उसकी पहचान नहीं पूछी थी। इसके अलावा ट्रेंन में और भी दाढ़ी व टोपी पहने मुसलमानी रिवास में लोग बैठे थे। बावजूद इसके चेतन ने अन्य किसी भी मुसलमानी लिबास वाले शख्स पर गोली नहीं चलाई। निश्चित रूप से यह कत्ल इंसानियत के खिलाफ है। जितनी हो सके इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य है। शासन के द्वारा फौरी तौर पर कारवाई करते हुए चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसपर कारवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है। फिलहाल चेतन सिंह जेल में है। बावजूद इसके इस मामले को सांप्रदायिक रंग देना नि:संदेह ओछी मानसिकता का परिचायक है।

आरोपी चेतन सिंह के पागलपन भरी मानसिक बीमारी की वजह से किए गये शूटआउट में 2 हिन्दुओं की भी जान गयी। चेतन ने अपने पागलपन के कारण तीन मुसलमान और दो हिन्दुओं को निशाना बनाया। वैसे इस वारदात में कुल छह लोगों की जान गयी है। ऐसे में इस बारदात को धार्मिक चश्मे से देखना और बताना कि यह किसी खास संप्रदाय के खिलाफ शासन के द्वारा की गई साजिश है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने के लिए अधिकतर राजनेता इस प्रकार के ब्यान जारी करते रहते हैं लेकिन इससे समाज और देश को बहुत घाटा होता है। इस प्रकार के ब्यान जारी करने से पहले देश, कौम और समाज को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के ब्यान को सेलेक्टिव कहा जाना चाहिए और इसे नफरती भी करार दिया जाना चाहिए। विगत लंबे समय से इस प्रकार के ब्यानबाजों को मुसलमानों का हितठेकेदार बता दिया जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के ब्यान देने वाले मुस्लिम नेता अंततः मुसलमानों का ही अहित करते देखे गये हैं।

इस मामले में अपने को मुसलमानों का हितचिंतक कहने वाले कई नेताओं ने साम्प्रदायिक ब्यान जारी किया है, जिसमें राणा अय्यूब, असदुद्दीन ओवैसी आदि कई नेता शामिल हैं। इनके जैसे कथित मुस्लिम हमदर्दो ने घटना के फौरन बाद अपनी घटिया सियासत शुरू कर दी। राणा अय्यूब ने अपने ट्वीट के जरिए एक सियासी जमात को निशाना बनाते हुए हेट स्पीच का हवाला देकर इस घटना को तूल दे सांप्रदायिक रूप देने की कोछी कोशिश की। वहीं ओवैसी साहब ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ एक आतंकवादी घटना करार दिया। हेट स्पीच को मुद्दा बनाते हुए राणा अय्यूब ने जिस प्रकार ट्वीट किया है, वह मात्र हेट स्पीच का मामला नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सियासी निशाना साधते हुए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है। ओवैसी वायरल वीडियो के आधार पर जिस कांस्टेबल चेतन सिंह के कथन को आधार बनाकर इसे आतंकी घटना बता रहे हैं, गौरतलब है कि चेतन मानसिक रूप से बीमार और अस्थिर चित्त का व्यक्ति है।

राणा अय्यूब और उनके जैसे लोग जिसको वाकई मुसलमानों की फिक्र होती और हेट स्पीच का मसला उनकी निगाह में महत्व रखता, तो वे सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते जो खुद को मुसलमान कहते हुए दूसरे फिरके के मुसलमानों को बिना वजह उनकी धार्मिक आस्था के आधार पर टारगेट करते हुए उनके खिलाफ नफरती ब्यानबाजी करते फिरते हैं। राणा अय्यूब को उन लोगों की भी खबर लेनी चाहिए जो अपनी मस्जिदों में यह बोर्ड लगा कर बैठे हैं कि किसी दूसरे फिरके के लोग इस मस्जिद में ना आये और अगर आ भी गये तो अपनी हालत के जिम्मेदार वे खुद होंगे। राणा साहब को वह बातें दिखाई नहीं देती कि जब किसी खास मसलक की मस्जिद में दूसरे मुसलमान पहुंच जाते हैं तो उस मस्जिद को धुलवाया जाता है। राणा अय्यूब साहब की निगाह में क्या वह बातें नहीं गुजरती कि जब हेट स्पीच के जरिए दूसरे फिरके के लोगों को दहशत का शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में मोहर्रम के दिन सूफी मुसलमानों के खिलाफ खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की। सूफियों के आस्था पर आघात किया गया।

संविधान और संवैधानिक मूल्यों की दुहाई देने वाले तथाकथित मुस्लिम नेता उस वक्त कहां चले जाते हैं जब खुद को मुसलमान कहने वाला एक मजहब जुनूनी टोला दूसरे मुसलमानों को उनकी धार्मिक आस्था के आधार पर उनका शोषण करता है। उनका अपमान करता है और उनके खिलाफ हिंसक वारदातों को अंजाम देता हैं। क्या राणा अय्यूब, ओवैसी और उनके जैसे लोग इस बात का जवाब देंगे? हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि इनका मुसलमानों से कोई लेनादेना है ही नहीं। ऐसे लोगों को मुसलमानों की परेशानियों से, उनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार के लोग, ऐसी घटनाओं के आधार पर एक दंतकथा गढ़ते हैं और अपने हित के लिए भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कथित मुसलमानों के नेता बस अपने हित के लिए कौम और मादरे वतन दोनों के साथ गद्दारी कर रहे हैं।

77वें स्वतंत्रता-दिवस

पहाड़ सी चुनौतियां, मज़बूत इरादे क़दम-दर-क़दम बढ़ रहा हिमाचल

-ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू-
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमें लम्बे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस का यह गौरवमयी ऐतिहासिक दिन हम सभी भारतवासियों के लिए उन वीर सपूतों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें आज़ादी दिलवाई।

आज़ादी की लड़ाई में हिमाचल के वीर सपूतों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में धामी गोलीकांड, प्रजामण्डल आन्दोलन, सुकेत सत्याग्रह और पझौता आन्दोलन का प्रमुख स्थान है। इस अवसर पर मैं, देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले वीर नायकों और नायिकाओं को सादर नमन करता हूँ।

देवभूमि के साथ-साथ हिमाचल को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के वीर जवान अपने अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। स्वाधीनता संग्राम से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा तक प्रदेश के जवानों ने वीरता का परचम लहराया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्तरा, कर्नल डी.एस. थापा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी उनके उल्लेखनीय पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाज़ा गया।

प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वाधीनता सेनानियों तथा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की पत्नियों को 15 हज़ार रुपये व उनकी अविवाहित बेटियों को 10 हज़ार रुपये हर माह प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के विवाह के लिए 51 हज़ार रुपये तथा पोतियों के विवाह के लिए 21 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी और अर्द्धसरकारी सेवा में दो प्रतिशत आरक्षण की सुविधा भी दी गई है।

प्रदेश में परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को तीन लाख रुपये तथा महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को दो लाख रुपये की सालाना राशि दी जाती है। वीर चक्र तथा शौर्य चक्र विजेताओं को एक लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं।

इस साल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने तबाही का भयानक मंजर दिखाया। यह पिछले कई सालों में सबसे बड़ी आपदा है जिसमें अनेक सड़कें, पुल, जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति योजनाओं को भारी क्षति पहुंची। असंख्य पर्यटक फंस गए और देश-दुनिया से सम्पर्क कट गया।

राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए रिकॉर्ड 48 घण्टों में सबसे अधिक प्रभावित कुल्लू घाटी में बिजली-पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कीं। सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ज़िला किन्नौर के सांगला से 125 लोगों को सुरक्षित निकाला।

एक अत्यंत कठिन बचाव अभियान के तहत माइनस 4 डिग्री तापमान में 14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर ज़िला लाहौल-स्पिति के चंद्रताल में फंसे 303 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। 4 फुट बर्फ की मोटी चादर को काटकर रास्ता निकाला गया। तड़के 2 बजे बचाव दल चंद्रताल पहुंचा और पर्यटकों को सुबह सात बजे 57 वाहनों के माध्यम से काजा के लिए रवाना किया गया। लोसर में अस्थाई राहत शिविर बनाया गया। आपदा के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में फंसे लगभग 75 हजार पर्यटकों को सुरक्षित निकाला।

मैं, प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से इस आपदा में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। विपदा की इस घड़ी में सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनों को खोया है।

हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में लगभग 8 हज़ार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। केन्द्र सरकार की टीम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने आई थी। मैंने स्वयं भी प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों से मिलकर आपदा से उत्पन्न स्थिति बयां की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपये की राशि तुरन्त जारी करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, मैंने राहुल गांधी जी से मिल कर उन्हें भी प्रदेश के हालात से अवगत करवाया। प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए **आपदा राहत कोष-2023** बनाया है। विपदा की इस घड़ी में लोग इस कोष में बढ़-चढ़कर अंशदान कर रहे हैं जो बहुत मददगार साबित हो रहा है। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

इस वर्ष आपदा के दौरान गम्भीर संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत के तौर पर दी जाने वाली राशि कई गुणा बढ़ाई है। पहले पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12500 रुपये तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10000 रुपये की मदद दी जाती थी। परन्तु इस दौरान भारी वर्षा से जिन परिवारों के घर पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें हमने एक-एक लाख रूपये की राहत राशि प्रदान की है।

दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान के एवज़ में 10000 रुपये की सहायता मिलती थी। इस दौरान जिनकी दुकानों और ढाबों को नुकसान हुआ है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक लाख रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25000 रुपये की मदद का प्रावधान था। परन्तु इस दौरान ऐसे प्रभावित परिवारों को 50000 रुपये दिए गए हैं। वहीं, कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से गाद आने पर पहले लगभग 1400 रूपये प्रति बीघा मुआवज़ा दिया जाता था। परन्तु इस दौरान ऐसी भूमि के लिए 5 हज़ार रुपये प्रति बीघा की दर से राहत राशि दी गई है।

कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3600 रूपये प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी। परन्तु इस दौरान 10000 रुपये प्रति बीघा की दर से राहत दी गई है। प्राकृतिक आपदा में किसानों-बागवानों की फसल को नुकसान पर 2000 रुपये प्रति बीघा की दर से राहत दी गई है।

राज्य सरकार ने सत्ता सम्भालते ही अनाथ बच्चों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्हें **चिल्ड्रन ऑफ स्टेट** का दर्जा दिया। उनके समग्र कल्याण के लिए **मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना** आरम्भ की और **मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष** की स्थापना की। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को गुणात्मक शिक्षा, मार्गदर्शन, करियर परामर्श, वस्त्र भत्ता जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। त्यौहारों पर भी इन बच्चों को 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विवाह अनुदान व मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। इन बच्चों को शैक्षणिक दौरे पर भेजने, कोचिंग दिलवाने, इनकी उच्च शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास आदि के लिए राज्य से बाहर भेजने का प्रावधान भी किया गया है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोज़गार के अवसर देने के लिए स्टार्ट-अप शुरू करने का भी योजना में प्रावधान है। अब इन बच्चों के माता-पिता सरकार ही है।

विधवाओं और एकल नारियों की मुश्किलों को समझते हुए सरकार ने **मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना** शुरू की है। योजना के तहत इस वर्ष 7 हज़ार ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में बदलाव करते हुए पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया गया है।

कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र के वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिकी मज़बूत करने, सभी वर्गों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जन हितैषी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को **पुरानी पैन्शन योजना** का लाभ देने का वायदा निभाया है। **युवाओं को रोज़गार** के अवसर सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल स्तर की उप-समिति गठित की गई है जो इसके लिए खाका तैयार कर रही है।

राज्य सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक **हरित ऊर्जा राज्य** बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। प्राइवेट ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ऑटो तथा ई-गुड्स कैरियर लेने पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में **रोबोटिक सर्जरी** की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअल्टी विभाग को **आपातकालीन चिकित्सा विभाग** में स्तरोन्नत किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को **आदर्श स्वास्थ्य संस्थान** के रूप में स्तरोन्नत करने की योजना है। गुणात्मक दवाइयां आधुनिक तकनीक सहित चिकित्सा उपकरण तथा अन्य मशीनरी की खरीद के लिए **हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम** का गठन किया गया है।

सुपर स्पेशेलिटी अस्पताल, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों में **हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम** शुरू किया जा रहा है। इससे रोगियों का पूरा डाटा एक ही स्थान पर मिल जाएगा।

सरकार ने प्रदेश में **राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल** आरम्भ करने का फैसला लिया है। गरीब मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, एम.बी.ए., बी.फार्मेसी, नर्सिंग, तथा पीएचडी आदि की पढ़ाई के लिए बैंकों से एक प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलेगा।

सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। प्रदेश में **'एक राज्य - एक पोर्टल'** प्रणाली लागू की जाएगी। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

किसानों के हित में सरकार हिम उन्नति योजना शुरू कर रही है। इसके तहत दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नगदी फसलों के कलस्टर बनाए जाएंगे। दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की **हिम गंगा योजना** आरम्भ की जाएगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रति किलो वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे बागवानों को लाभ मिल रहा है।

हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार साहसिक धार्मिक एवं **ईको-टूरिज़्म** के विस्तार के लिए पर्यटन अधोसंरचना को विकसित कर रही है। ज़िला कांगड़ा को **हिमाचल की पर्यटन राजधानी** के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 3 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और सभी ज़िलों में हेलीपोर्ट स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रदेश में बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों पर हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना** आरम्भ की गई है। इससे तीखी ढलानों में मिट्टी धंसने की घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

सरकारी कामकाज में **ई-गवर्नेंस प्रणाली** लागू की जा रही है। इससे कार्य निष्पादन में दक्षता आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। **ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना** के तहत 34 विभागों की 184 नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदेशभर में लोगों को 71 ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं। **'हिम परिवार'** के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध होगा।

राज्य सरकार **ड्रोन नीति** तैयार कर रही है। पायलट आधार पर कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों द्वारा दी गई असंख्य कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें कोटि-कोटि नमन। आईए! इस पावन अवसर पर यह संकल्प लें कि देश की एकजुटता, समरसता, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना रचनात्मक सहयोग देंगे और प्रदेश की तरक्की व खुशहाली के लिए तन, मन व धन से समर्पित प्रयास करेंगे। स्वाधीनता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द! जय हिमाचल!

सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपये जारीः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का विस्तृत जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता

प्रदान करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों को समयबद्ध बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत तुरंत अल्पकालिक निविदा जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि दाग वाले सेब के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेब उत्पादक लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छैला-यशवंत नगर सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 70 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे और यह सड़क शिमला के ऊपरी क्षेत्र के लोगों के लिए चंडीगढ़ तक यात्रा के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के लिए दक्षतापूर्वक कार्य कर रही है, ताकि सड़क सम्पर्क के अभाव में बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपये जारी किए हैं और पर्याप्त मशीनरी भी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण संपर्क सड़कों का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और उन्हें बहाल करने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों से सेब सीजन के लिए अस्थायी सड़कें बनाने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया। इससे किसानों के उत्पाद समय पर बाजार तक पहुंच सकेंगे और राज्य सरकार उन्हें उचित मुआवजा देगी।

उन्होंने भारी बारिश के कारण प्रभावित चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुड़ी गांव को स्थानांतरित करने और लोगों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर निरंतर शिमला जिला के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वह स्वयं भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने स्वयं प्रदेश के कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और वह शिमला के ऊपरी क्षेत्रों के दो दिवसीय दौरे के दौरान बहाली कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि हाल की त्रासदी में हिमाचल प्रदेश को लगभग 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस आपदा से राज्य के सभी क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है और यह 50 वर्षों के दौरान हुई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को भारी कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन प्रभावित परिवारों की मदद के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि चौपाल में अब केवल दो सड़कें बंद हैं, बाकी सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को स्थायी रूप से बहाल करने के दृष्टिगत सुरक्षा दीवार लगाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौपाल क्षेत्र के 300 घर आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने प्रशासन को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रत्येक को एक लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्त को बलसन क्षेत्र की 15 पंचायतों के संपर्क मार्गों की बहाली के लिए 3-3 लाख रुपये उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने चौपाल में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बहाली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल एक लाख मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चौपाल मण्डल में सड़क संपर्क बहाल करने के लिए 2 करोड़ रुपये और ठियोग के सैंज उप-मण्डल के लिए 50 लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए जबकि 1.50 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने चौपाल में कालेश्वरी माता मंदिर दियुन्दर में पूजा-अर्चना भी की।

सड़कों की मरम्मत के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी राज्य सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपरी शिमला के दो दिवसीय दौरे के बाद जिला शिमला में सम्पर्क मार्गों की मुरम्मत के कार्य में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला के विधानसभा क्षेत्र चौपाल, जुब्बल कोटखाई और रोहडू में पंचायत स्तर तक प्रभावित सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 1.65 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास खण्ड जुब्बल, कोटखाई, रोहडू और छौहारा के लिए प्रति ब्लॉक 30 लाख रूपये आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त चौपाल विधानसभा क्षेत्र के बलसन की 15 पंचायतों के क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की तुरन्त मरम्मत करने के लिए 45 लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी गई है, जिससे मरम्मत के कार्य में तेजी आएगी और बागवानों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सेब उत्पादक क्षेत्रों से किसानों के उत्पादों को मण्डियों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सम्बन्धित विभागों को सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेब का सीजन चरम पर पहुंचने से पहले 15 अगस्त तक सभी सम्पर्क सड़कों को दुरूस्त करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बागवानों की किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी।

पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है मन भावन हिमाचलः सुन्दर सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश भारी प्राकातिक आपदा से जूझ रहा था। इस त्रासदी से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा परन्तु सरकार की प्रतिबद्धता से रिकॉर्ड समय में सड़क,स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को बहाल किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गो सहित सम्पर्क सड़कों को पुनः बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार पयर्टकों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहां कि मन भावन वादियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे दूर-दराज क्षेत्रों में होटलों व होम-स्टे इत्यादि में पर्यटकों ने भारी तादाद में बुकिंग करवाई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कांगड़ा, कुल्लू-मनाली और जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डों के लिए हवाई सेवाएं निरन्तर जारी हैं। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश में आपदा के उपरान्त स्थितियां अब सामान्य हो चुकी हैं। पर्यटकों की सुरक्षा प्रदेश सरकार का दायित्व है।प्रदेश सरकार पर्यटकों को हिमाचल भ्रमण के लिए आमंत्रित करती है और राज्य पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

प्रभावित बागवानों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करेगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लैला में हाल ही में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आपदा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया और परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने उपमंडलाधिकारी (ना.) रोहडू को 12 घंटों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें प्रभावित परिवारों को देय वित्तीय सहायता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह यहां प्रभावितों का दुःख-दर्द साझा करने आये हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब के बागीचों को हुए नुकसान के व्यापक आकलन का कार्य प्रगति पर है और प्रभावित बागवानों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत नियमावली में संशोधन कर मुआवजा राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया है और नये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जायेगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने लैला में क्षतिग्रस्त नाले के तटीयकरण की शीघ्र बहाली और बादल फटने के कारण क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय की दीवार की शीघ्र मरम्मत का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटना में कई घरों में मलबा घुस गया है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों का हरसंभव सहयोग कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह स्वयं और सभी मंत्री सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर पीड़ितों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों के साथ एकजुट खड़े रहने के यह प्रयास सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, उपायुक्त आदित्य नेगी, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने रामपुर, ठियोग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का लिया जायजा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में बारिश से हुए भारी नुकसान का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें आपदा से अवरुद्ध हुई सड़कों, बाधित पेयजलापूर्ति, मकानों को पहुंचे नुकसान के बारे में अवगत कराया। ग्राम पंचायत ननखड़ी में महिलाओं की सड़क मार्ग बहाल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनका दुःख-दर्द समझते हैं, अवरुद्ध पड़े रास्तों को खोलने के लिए पंचायतों को भी आवश्यक धनराशि जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग सड़कों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को थाना ननखड़ी, बड़ोग और कुंगन बाल्टी पंचायतों में बारिश से क्षतिग्रस्त 50 से अधिक मकानों के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ोग पंचायत के पूनन गांव और बगलती पंचायत के जवाल्डा गांव में बारिश, भूस्खलन से पूरी तरह व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी प्रभावितों को एक-एक लाख रुपये तुरंत देने को कहा। खोलीघाट में भी उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही एक बार फिर क्षेत्र के दौरे पर आएंगे और उनके निर्देशों पर

हुई कारवाई की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सेब क्षेत्र में पंचायतों से सड़क बहाली का काम तेज करवाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित जरोल, खनेटी और कोटगढ़ क्षेत्रों का दौरा कर भी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत जरोल के 8 सम्पर्क मार्गो की मरम्मत के लिए 5 लाख रूपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की।

आपदा प्रभावित लोगों ने अपनी व्यथा सुनाने के साथ ही राहत नियमावली में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के लिए फौरी राहत राशि को दस से बीस गुणा बढ़ाकर देने का निर्णय सराहनीय है।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक नंद लाल व कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह श्याम, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जल संसाधन ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक निधि प्रदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की तथा इस अवसर पर आयोजित बैठक में प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

उप-मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश एवं भू-स्खलन इत्यादि से हुए नुकसान के बारे में केन्द्रीय

मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ भागों में पिछले सौ वर्षों की अवधि में सर्वाधिक बाढ़ का प्रकोप इस वर्ष झेलना पड़ा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं और जल संसाधन ढांचों के पुनर्निर्माण में केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्रदान करने का आग्रह किया।

अग्निहोत्री ने कहा कि अभी तक जल शक्ति विभाग को लगभग 1630 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश में जलापूर्ति ढांचे की बहाली के लिए उदारतापूर्वक त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रारम्भिक तौर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली तथा रेट्रोफिटिंग के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि तुरन्त जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने जल जीवन मिशन की शत प्रतिशत क्षतिग्रस्त योजनाओं को नए तरीके से स्थापित करने और इसके लिए आवश्यक निधि जारी करने का भी आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस त्रासदी में प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है और वह केन्द्रीय वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के समक्ष मामला उठाएंगे ताकि अपेक्षित सहायता प्रदान की जा सके।

अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश से भारी क्षति हुई है लेकिन ब्यास नदी के किनारों पर सर्वाधिक नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि इस नदी बेसिन में इस तरह की आपदाओं का इतिहास रहा है और जल शक्ति विभाग ने इसके तटीयकरण के लिए 1699 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, इसके लिए केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे (सीडब्ल्यूपीआरएस) के सहयोग से मानक अध्ययन किया गया है। वर्तमान में यह प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग के समीक्षाधीन है।

उप-मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इसे शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया ताकि कुल्लू-मनाली सहित इस नदी घाटी के आसपास बसे लोगों के बहुमूल्य जीवन और सम्पदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ब्यास नदी के तटीयकरण पर बल देते हुए कहा कि यह कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे के सामरिक उपयोग के दृष्टिगत भी आवश्यक है तथा चण्डीगढ़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग भी ब्यास नदी के किनारे से होकर गुजरता है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्यास के तटीयकरण से पर्यटकों को आवाजाही की सुगमता होगी और कुल्लू तथा लाहौल घाटी से बागवानी उत्पादों को बाहर की मंडियों तक ले जाने में भी बेहतर व सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कांगड़ा जिला में 643 करोड़ रुपये की फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना और ऊना जिला में ब्यास नदी बेसिन की स्वां नदी के 339 करोड़ रुपये के तटीयकरण के लिए निवेश मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दोनों परियोजनाएं काफी समय से लंबित थी। उन्होंने केन्द्र सरकार से इनके लिए आवश्यक धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया ताकि इन पर कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जारी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया तथा ऊना जिला के बीत और कुटलैहड़ क्षेत्र में नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के हिमाचल दौरे के दौरान निर्धारित प्राथमिकताओं पर प्रदेश ने तीव्रता से कार्य किया है। इसके अंतर्गत जलशक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने लेह और लद्दाख का दौरा कर वहां एंटी फ्रीज जलापूर्ति प्रणाली का अध्ययन किया है और विभाग ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए ऐसी 17 योजनाओं के लिए 101.58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए हैं। उन्होंने इन योजनाओं को जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत करने का आग्रह भी किया। इसके अतिरिक्त राज्य में जल की कमी वाले क्षेत्रों को स्रोतों का पुनर्भरण करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 452.60 करोड़ रुपये के 45 प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे इन जलापूर्ति योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए सीधे भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण सुनिश्चित हो सकेगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने किन्नौर जिला के चांगों क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से भी केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया और कहा कि इसे समीक्षा के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है और आयोग से टिप्पणी प्राप्त होने के उपरान्त लगभग 61 करोड़ रुपये के ऐसी 20 सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए तैयार हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इन परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। केन्द्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा उठाते हुए राज्य से बिजली की कीमतों से संबंधित मामले को सुलझाने और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए लम्बी अवधि के विशेष ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत करने का आग्रह किया ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र शुरू किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हिमाचल इस बारे में प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगा।

बारिश में हुए नुक़सान से राहत के लिए गिरिराज सिंह से मिले अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिले। अनुराग

सिंह ठाकुर ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री से भेंट के दौरान बारिश व बाढ़ से हिमाचल में सड़कों व घरों को हुए नुक़सान से राहत देने का अनुरोध किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने गिरिराज सिंह जी से प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर की सड़कें व आवास योजना में 5000 घरों के निर्माण की माँग की। ग्रामीण विकास मंत्री ने अनुराग ठाकुर की 2700 किलोमीटर सड़क निर्माण की माँग को तत्काल सहर्ष स्वीकार कर लिया।

अनुराग ठाकुर ने गिरिराज सिंह को हिमाचल में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान से भी अवगत कराया। इस भेंट के दौरान भाजपा हिमाचल के वरिष्ठ नेता व नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा जी भी उपस्थित रहे।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक जटिलता और मौसम के बदलाव के समय विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में भारी बारिश व बाढ़ के चलते जान-माल और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुक़सान हुआ है। जगह जगह सड़कें टूटने लोगों के घरों के टूटने की घटना दुखदाई है। इस बार की बारिश ने उन सड़कों-घरों-पुलों को नुक़सान पहुँचाया है जहां पहले कभी बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा। उन्होने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से हुए नुक़सान के बारे में जानकारी दी।

अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री के समक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़कों के बारिश में बह जाने का विषय प्रमुखता से उठाया। उन्होने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया की हिमाचल के ग्रामीण इलाक़ों में जो सड़कें बाढ़ के कारण बह गई हैं उनके पुनर्निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाये ताकि लोगों की आने जाने की समस्या समाप्त हो व सामान्य जनजीवन पहले की तरह बहाल हो।

अनुराग ठाकुर ने गिरिराज सिंह से ग्रामीण इलाक़ों में बारिश से जिन लोगों के घर गिरे है उन्हें प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत घर बना कर दिया जा सके विषय पर भी व्यापक चर्चा की। उन्होने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 5000 घरों के निर्माण की माँग रखी जिसे स्वीकार कर लिया है। उन्होने बताया कि पिछले 9 वर्षों में हिमाचल में प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत 15331 घरों का निर्माण हुआ है और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हिमाचल में लगभग 21 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा का सड़क निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है।

राज्य सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धः शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय में इन बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद इन बच्चों के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' और 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष' शुरू की गई।

मंत्री ने अधिकारियों को योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र बच्चे को इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा, कौशल विकास के अवसर, करियर परामर्श, विवाह अनुदान, घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से इन बच्चों को जीवन में उपयोगी कार्य करने में मदद मिलेगी जिससे समाज को लाभ होगा। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम. सुधा देवी, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत के. शर्मा, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कुमार, निदेशक प्रदीप कुमार, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास मोहन दत्त एवं अतिरिक्त सचिव वित्त विनय कुमार इस बैठक में उपस्थित थे।

10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र किए जाएंगे जारीःरोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अंतर्गत परीक्षा पास करने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को वर्ष 2023 से उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए केवल अंक तालिका व प्रवास प्रमाण-पत्र ही उपलब्ध करवाये जाते थे, जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य बोडों द्वारा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र भी छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी पूर्व में यह सुविधा केवल आग्रह पर ही उपलब्ध करवाता था। इस कारण प्रदेश से बाहर रोजगार के लिये जाने वाले युवाओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। उनके आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आकर यह प्रमाण-पत्र बोर्ड कार्यालय में आकर ही लेना पड़ता था। विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र देने का निर्णय लिया है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

www.shailsamachar.com

प्रकृति से ज्यादा सरकार की योजनाएं जिम्मेदार रही है इस विनाश के लिये

- मौत की भरपाई कोई निर्माण नहीं कर सकता यह समझना होगा।
- एन.जी.टी. के फैसले की अनुपालना क्यों नहीं हो रही?
- सारा विनाश जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन निर्माण क्षेत्रों में ही क्यों हुआ।

शिमला/शैल। इस बार भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उससे प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा है। सैकड़ो के हिसाब से इंसान और पशु मारे गये हैं। कई जगह पूरे के पूरे गांव तबाह हो गये हैं। पूरे नुकसान के पूरे आंकड़े आने में लम्बा समय लगेगा। सरकारी और निजी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में दसकों लग जायेंगे। पूरे प्रदेश में सारे शिक्षण संस्थान एक साथ बन्द करने पड़े हैं। शिमला में ही एक मंदिर में एक साथ इतने लोगों का दब जाना और शहर की हर मुख्य सड़क का ब्लॉक हो जाना अपने में ही कुछ ऐसे सवाल खड़े कर जाता है जिन्हें टालना भविष्य के और नुकसान को न्योता देना होगा। क्योंकि जिस शिमला को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा हो जब वही प्रकृति का बंधक होकर रह जाये तो यह सोचना ही पड़ेगा कि यह सब एक साथ कैसे घट गया? क्या इसके लिये हमारी नीतियां और महत्वकांशायें भी जिम्मेदार नहीं रही है। क्योंकि हिमाचल भूकंप जोन चार और पांच में आता है। विभिन्न संस्थानों के अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर माह छोटे स्तर के पांच भूकंप के झटके आते हैं। वाडिया संस्थान देहरादून के मुताबिक अक्तूबर 2021 से मार्च 2023 तक प्रदेश में भूकंप के 87 झटके आ चुके हैं। ऊना को छोड़कर हर जिले में यह झटके आये हैं। आंकड़ों के अनुसार चम्बा 26 मण्डी 15 किन्नौर 12 शिमला 11 कांगड़ा 7 लाहौल-स्पीति 4 कुल्लू 4 सिरमौर 3 हमीरपुर 2 बिलासपुर 2 सोलन 1 और ऊना 0। अध्ययन के अनुसार छोटे झटकों से भूस्खलन आता है।

इन आंकड़ों के साथ ही जल विद्युत अध्ययन और कार्यरत योजनाओं के आंकड़ों पर भी नजर डालना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हिमाचल को जल विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया है। हिमाचल में 27436 मैगावाट जल विद्युत चिन्हित की गयी है। इसमें से 24000 मैगावाट का दोहन योग्य करार दिया गया है। 20912 मैगावाट की परियोजनाएं निर्माण के लिये आबंटित भी हो चुकी है और 10519 मैगावाट की परियोजनाएं उत्पादन में आ चुकी हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण में जो बांध बनाये गये हैं जो सुरगें निकाली गयी हैं उसमें हुये खनन से जो लाखों टन मालवा निकला है उसे कहां डाला गया? इनके लिये जो सड़क निर्माण हुआ उसमें जो पेड़ और पहाड़ काटे गये क्या उससे पर्यावरण प्रभावित नहीं हुआ? 2010 में प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी एक याचिका में अदालत ने इस सबके अध्ययन के लिये एक शुक्ला कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में आया है की चम्बा में रावी पर बन रही परियोजनाओं में 65 किलोमीटर तक रावी अपने मूल स्वरूप से गायब है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जो दिशा-निर्देश सरकार और विद्युत निर्माता कंपनियों को दिये हैं उन पर आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है।

राजधानी शिमला में ही अवैध निर्माणों को प्रोत्साहन देने के लिए नौ बार रिटैन्शन पॉलिसीयां लायी गयी हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एन.जी.टी. और सर्वोच्च न्यायालय तक इस पर गंभीर टिप्पणियां कर चुके हैं। दोषियों को नामत: चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश तक अदालत दे चुकी है। लेकिन किसी भी सरकार ने यह कारवाई करने का साहस नहीं किया है। सारी सरकारें इसके लिये बराबर की दोषी रही हैं। एन.जी.टी. ने नवम्बर 2016 में शिमला में नये निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया था। शिमला में ढाई मंजिल से अधिक का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाबजूद अदालत में. आये रिकॉर्ड के मुताबिक तीस हजार के करीब अवैध निर्माण हो चुके हैं। इसी का संज्ञान लेते हुये शीर्ष अदालत ने शिमला प्लान को अभी अनुमोदित नहीं किया है। लेकिन सुक्खू सरकार ने भी अवैधता को आगे बढ़ाते हुये ऐटीक फ्लोर को रिहाईशी योग्य बनाने और बेसमैन्ट को खोलने के आदेश नगर निगम चुनाव में कर दिये। ए.जी.टी.का फैसला प्रदेश सरकार की अपनी रिपोर्ट पर आधारित है। तरुण कपूर जो इस समय प्रधानमंत्री के सलाहकार भी है उनकी रिपोर्ट एन. जी.टी. के फैसले का बड़ा आधार है।

यह सारी चर्चा इसलिये आवश्यक है क्योंकि इस आपदा में जो नुकसान है उसका बड़ा क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन सड़कों का निर्माण क्षेत्र रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विनाश के लिये सरकार की योजनायें सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है। क्योंकि भूकंप के लिये हुये अध्ययनों में साफ कहा गया है कि इसके लिये जलविद्युत परियोजनाओं और सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिये हुआ अवैज्ञानिक खनन जिम्मेदार है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने भी इस विनाश के लिये अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। इस परिदृश्य में भविष्य के लिये जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन सड़कों के निर्माण पर नये सिरे से विचार करना होगा। क्योंकि मौत की भरपाई कोई निर्माण नहीं कर सकता।

फोरलेन निर्माता कंपनियों के खिलाफ आयी शिकायत पर कारवाई कब

- क्या इन निर्माणों में पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट अथॉरिटी की भी कोई भूमिका है
- क्या इन निर्माता कंपनियों के साथ निगरान तंत्र की भी भूमिका नहीं है

शिमला/शैल। परमाणु-सोलन और किरतपुर-मनाली फोर लेन पर इस वर्षा के कारण जितना नुकसान हुआ है क्या उसके लिये इन फोर लेन निर्माता कंपनीयों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का भूस्खलन हुआ है उसका कारण पहाड़ों का अवैज्ञानिक कटान माना जा रहा है। परमाणु-सोलन में जाबली के पास एक पूरा गांव नष्ट हो गया है। मण्डी-कुल्लू में भी पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण मौतें हुई हैं। अवैज्ञानिक कटान आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आता है और दण्डनीय अपराध है। परमाणु- सोलन निर्माण पर सवाल उठाते हुये शिमला के पूर्व उप महापौर सी.पी. एम. नेता टिकेन्द्र पंवर ने परमाणु पुलिस के पास निर्माता कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर कंपनी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किये जाने की मांग की है। मण्डी में भी सी.पी.एम. नेताओं ने किरतपुर-मनाली फोर लेन निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने की मांग की है। पुलिस द्वारा अभी तक यह सामने नहीं आया है कि उसने इन शिकायतों पर क्या कारवाई की है। लेकिन इस संबंध में आये हर अध्ययन में यह माना गया है कि इस नुकसान का बड़ा कारण अवैज्ञानिक कटान रहा है।

निर्माता कंपनियों के खिलाफ आयी शिकायतों के साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इसके लिये केवल यह निर्माता कंपनियां ही जिम्मेदार हैं या प्रदेश सरकार के तंत्र की भी इसमें कोई जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए प्रदेश में पर्यावरण विभाग स्थित है। जब भी किसी नई परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसकी स्वीकृति दिये जाने से पहले पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट रिपोर्ट ली जाती है और रिपोर्ट देने के लिये इस आश्य की एक अथॉरिटी भी गठित है। इस अथॉरिटी की रिपोर्ट के बिना किसी भी योजना की अनुमति नहीं मिल पाती है चाहे कोई उद्योग लगाना हो कोई सड़क निर्माण होना हो या कोई विद्युत परियोजना का प्रस्ताव हो।

इस अथॉरिटी की रिपोर्ट के बाद जब निर्माण शुरू हो जाता है तो समय-समय पर यह देखना की निर्माण में तय मानकों की अनदेखी तो नहीं हो रही है। ऐसे में जब फोर लेन निर्माता कंपनियों पर अवैज्ञानिक कटान के आरोप लग रहे हैं तब क्या सारी निगरान एजैन्सियों की भूमिका भी स्वत: ही जांच के दायरे में नहीं आ जाती है? अब जब सी.पी.एम. नेताओं ने निर्माता कंपनियों के खिलाफ शिकायत करके जांच किये जाने की मांग उठा दी है तो क्या उसी तर्ज पर संबद्ध निगरान एजैन्सियों की भी जांच नहीं हो जानी चाहिये।